कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कमलादेवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

Web site – www.govtkdmcollegerjn.com ☎ **Phone No.– 07744-225171**
Email –kamlacollege.rjn@gmail.com 🖷 **Fax No. – 07744-225171**

''कमला कॉलेज में नई शिक्षा नीति पर हुआ विमर्श''

शासकीय कमलादेवी राठी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप पर आज दिनांक 16.07.2019 को 03:00 बजे महाविद्यालय में एक विमर्श का आयोजन किया गया । जिसमें शिक्षाविद् डॉ.गणेश खरे ने कहा कि आज ही तीन खबरे मैने पढ़ा कि प्राईमरी स्कूल में शिक्षक नहीं है । एक महाविद्यालय में कक्षा में दरवाजा नहीं है और एक विश्वविद्यालय द्वारा जो परिणाम जारी किया गया है । उसमें एक विषय के अंक ही जोड़े नहीं गए है अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या हो रहा है ? अध्यापन का कार्य का समय कम है और अन्य कार्यो में समय अधिक दिया जा रहा है । परीक्षा की अवधि ही लगभग 06 महीने की है । 1970 में जो पाठ्यक्रम था वही कमोबेस आज भी चल रहा है । अतः नई शिक्षा नीति में कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए और व्यक्तित्व का उन्नमुखीकरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रखते हुए गुणनात्मकता बढ़ाई जाना चाहिए । महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ.एम.एल.साव ने कहा कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में गुणनात्मक परिवर्तन आएगे और GER 50 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करेंगा । महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ.एच.के.गरचा ने कहा कि प्रायमरी एजुकेशन में जनरल प्रमोशन की नीति को बंद करना चाहिए । सुश्री आबेदा बेगम ने सवैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रश्नों का समावेश कर शिक्षण पद्धति का विकास करने पर जोर दिया । कार्यक्रम के संयोजक डॉ.ओंकार लाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभी नई शिक्षा नीति से भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था फिर से नालंदा और तक्ष्यशिक्षा की तरह अपने गुणवत्ता पूर्ण ऊचांईयों पर पहुचेगी । अब पाठ्यचर्या का विकास व्यवहारिक शिक्षण आधारित होने जा रहा है जिसमें कल्पनाशील और लचीली पाठ्यचर्या की संरचना अपनाई जाएगी । एम.फिल खत्म किया जाएगा, च्वाईस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम को और संशोधित किया जाएगा । तदर्थ संविदा नियुक्ति पर रोक लगाई जाएगी । उच्च शिक्षण संस्थानों में टीचर जो पढ़ाने आएगे उनकी ट्रेनिंग के बाद ही पढ़ाएगें जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी । डॉ.जी.पी.रात्रे ने कहा कि वंचित वर्ग को भी शिक्षा अच्छे से मिल सके तथा 12 वर्ष तक के बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए । शिक्षा के क्षेत्र में निवेश और

अधिक होना चाहिए । डॉ.निवेदिता ए.लाल ने कहा कि प्रायमरी स्कूल से अंग्रेजी विषय का अध्यापन कराया जाना चाहिए । न्यूनतम उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 50 होना चाहिए, सभी पदों पर टीचर की नियुक्ति होना चाहिए । श्रीमती ममता आर.देव ने कहा कि फर्नीचर और टीचर की कमी दूर हो, अवासीय महाविद्यालयों तथा विद्यालयों की स्थापना हो, लाईब्रेरी देर रात तक खोली जाए । पढ़ाई के साथ स्कील डेवलपमेंट होना चाहिए । श्री महेन्द्र कुमार मेश्राम ने कहा कि कम्प्यूटर व स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को आधुनिक विज्ञान की शिक्षा मीडिल क्लास से देना शुरू की जाना चाहिए जिससे बच्चा नई तकनीकी चीजों को जान सकें । श्रीएस.एन.वानखेड़े ने कहा कि शिक्षा नीति प्रत्येक राज्य के एक ही होनी चाहिए और तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए । डॉ.सुषमा तिवारी ने कहा कि स्नातक स्तर में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा लिया जाना चाहिए और प्रायमरी स्कूल के शिक्षकों से अन्य कार्य नहीं करना चाहिए जिससे विद्यार्थी की नीवं मजबूत हो सके । श्री के.के.द्विवेदी ने कहा कि उच्च शिक्षा का अनिवार्य नहीं किया जाए, विशेषज्ञ शिक्षा पर जोर दिया जाए, मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य हो। स्नातकोत्तर शिक्षा अवासीय हो । पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय विशेषताएं शामिल होना चाहिए । श्री आलोक जोशी ने कहा कि साक्षरता की अवधारणा बदलनी चाहिए । ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई ही उत्तम है, शोध अपनी ही भाषा में व्यक्त करने की छूट होना चाहिए । शिक्षकों पर अन्य कार्यो का भार नहीं हो चाहिए । डॉ.बृजबाला उइके ने कहा कि पाठ्यक्रम रोजगारउन्नमुख होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पदों की पूर्ति होना चाहिए । डॉ.लाली शर्मा ने कहा नैतिक शिक्षा एवं योग शिक्षा का प्राथमिक कक्षाओं से ही समावेश किया जाना चाहिए । आठवी से ही कौशल विकास को जोड़ना चाहिए जिससे की वो रोजगार का अपना सके । सुश्री रेणु त्रिपाठी ने कहा कि प्रायमरी एवं मीडिल स्कूल में जनरल प्रमोशन नही होना चाहिए, छात्राओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ड्रापाउड रेट अभी भी अधिक है । डॉ.नीता एस.नायर ने कहा कि खेल कूद को प्रायमरी स्कूल से ही अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा चाहिए , खेल, एनसीसी, एनएसएस से जुड़े विद्यार्थी को प्रवेश में छ्ट दी जानी चाहिए और रिटार्यमेंट की उम्र घटाकर 60 साल किया जाना चाहिए जिससे नए युवाओं को रोजगार मिल सके । श्रीमती सुजाता ठाकुर ने कहा कि छात्र–छात्राओं को बचपन से ही ग्रंथालय जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए ।